



सांस्कृतिक रूप से वंचित माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप

मुकेश बुगालिया

शोधार्थी, शिक्षा विभाग

टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर, राजस्थान

शोध पर्यवेक्षक

प्रोफेसर (डॉ.) यशोदा चौहान

शिक्षा विभाग

टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर, राजस्थान

सार

यह अध्ययन सांस्कृतिक रूप से वंचित माध्यमिक विद्यालय पुपिल्स द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दूर करने के लिए एक शैक्षिक मार्गदर्शन कार्यक्रम तैयार करने का एक प्रयास था। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक रूप से वंचित माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की पहचान करना था। अन्वेषक ने सांस्कृतिक प्रतिकूलता की रुग्ण स्थिति के निवारण में विकसित शैक्षिक मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रभावकारिता को साबित किया। शैक्षिक मार्गदर्शन को "विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली सहायता के रूप में परिभाषित किया गया है जो स्कूलों में उनके समायोजन, पाठ्यक्रम और स्कूल के चयन के लिए अपेक्षित था"। यह एक प्रकार का मार्गदर्शन है जो किसी की अपनी क्षमताओं और क्षमताओं के अनुसार अलग-अलग वातावरण में अच्छी तरह से समायोजित करने में मदद करता है। यह छात्रों में विकसित करने की कोशिश करता है, उनमें आवश्यक जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करके स्कूल के माहौल को प्रभावी ढंग से समायोजित करने की क्षमता। इस प्रयास ने उन्हें उपयुक्त शिक्षण उद्देश्यों, उपकरणों और स्थितियों का चयन करने के लिए कैपेसिट किया।

मुख्य शब्द: सांस्कृतिक, माध्यमिक विद्यालय

परिचय

"शिक्षा सामाजिक मुक्ति का एक बड़ा साधन है जिसके द्वारा एक लोकतंत्र अपने सदस्यों के बीच समानता की भावना को स्थापित करता है, बनाए रखता है और उसकी रक्षा करता है," 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की घोषणा की, यह वास्तव में भारतीय शिक्षा के एक मिशन के बयान के समान है। स्वतंत्रता के बाद का युग। तत्कालीन नवजात भारतीय लोकतंत्र ने लाखों लोगों के दिमाग को घरेलू और औपनिवेशिक निराशाजनक कारकों द्वारा लगाए गए अभाव और पिछड़ेपन के चंगुल से मुक्त करने की दृष्टि से शिक्षा का निर्माण शुरू किया। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका के लिए, मैक्सिमम हैथ्रो है: शिक्षा उपकरण है; लक्ष्य से मुक्ति। सोशियो मुक्ति को समाज के एक समतावादी लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए साइन क्वालिफिकेशन नॉन माना



जाता है।

स्वतंत्रता के बाद के युग में भारतीय शिक्षा ने अब तक अपने अनुकरणीय प्रक्षेपवक्र को संभ्रांतवादी हस्तक्षेपों और धमकी के बावजूद भी बरकरार रखने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। इस भावना के लिए सबसे अकाट्य गवाही 2002 में भारतीय संविधान में ऐतिहासिक अनुच्छेद 21 ए और भारतीय संसद में द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंप्लेसरी एजुकेशन एक्ट, 2009 के तहत पारित करके भारतीय संविधान का ऐतिहासिक 86 वां संशोधन है। अनुच्छेद 21 छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार शिक्षा का अधिकार एक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार बन गया है और इसलिए यह उचित है। संशोधन अधिनियम की एक अन्य मुख्य विशेषता अनुच्छेद 45 के लिए एक नए लेख का प्रतिस्थापन है। नया लेख सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान की परिकल्पना करता है, जब तक कि वे छह साल की आयु पूरी नहीं कर लेते। इस के लिए उद्देश्य संशोधन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई अधिनियम) 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ और इसे सुरक्षित रूप से भारतीय शिक्षा के 'मैग्रा कार्टा' के रूप में करार दिया जा सकता है। पहुंच, इकित्ती और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए, यह भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं और अपर्याप्तताओं को संबोधित करता है। भारत चरम और विरोधाभासों से भरा देश है। यह सामाजिक वास्तविकताओं के लिए भी सही है। विकासात्मक लकुना लोगों के अलग-अलग वर्गों में मौजूद हैं- जाति-वार, समुदाय-वार, क्षेत्र-वार, आय-वार इत्यादि। तथ्य यह है कि ये सभी अंतर स्वाभाविक रूप से शिक्षा की अवधारणा और निष्पादन में परिलक्षित होते हैं। परिणामी पिछड़ापन और अभाव देश की सामाजिक वृद्धि और विकास को बाधित करते हैं।

शिक्षा भारत की विकासात्मक प्रक्रिया, इसके वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, सामाजिक-आर्थिक विकास, उर्ध्व सामाजिक गतिशीलता और सुरक्षा के लिए बुनियादी है। यह एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता और पूर्णता की खोज में व्यक्ति के परिवर्तन में, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शिक्षा को रोशनी और शक्ति का एक स्रोत माना जाता है जो हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति संकायों के प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास द्वारा हमारी प्रकृति को बदल देता है और सक्षम बनाता है (अल्टेकर एएस, 1934)। शिक्षा ज्ञान है। यह मनुष्य की तीसरी आँख है। शिक्षा के माध्यम से मानव जीवन के हर पहलू का विकास संभव हो जाता है। भारत केवल एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य नहीं है, बल्कि एक देश है जो परंपरागत रूप से लोकतंत्र की ओर झुका हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान, समान दर्जा और अवसर की गारंटी और दी जाती है क्योंकि किसी को भी धर्म, जाति, जाति, समुदाय, लिंग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकतंत्र के इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत में शिक्षा कहीं और भी



आवश्यक है, एक ऐसी सच्चाई जिसे भारतीय लोगों को महसूस करने की जल्दी है। भारतीय संविधान लोकतंत्र के आदर्शों को स्वीकार करता है; यह शिक्षा पर विचार करता है राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण आदानों में से एक है जो किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती है- आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक। ज्यां द्रेज़ और अमर्त्य सेन (1995) ने देखा है कि शिक्षा लोगों को अपनी क्षमताओं का निर्माण करने में सक्षम बनाती है, जिससे उनकी हकदारी को व्यापक बनाया जाता है और स्वतंत्रता के विस्तार में सुविधा होती है, जो विकास का प्राथमिक अंत और प्रमुख साधन है। प्रबुद्ध नागरिक एक समाज की सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं; यह लोकतांत्रिक आदर्शों और मानवीय मूल्यों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। आज सभी राष्ट्र इस लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं; विकसित, विकासशील और पिछड़े देशों ने शिक्षा के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए उपायों में वृद्धि में अपने कीमती संसाधनों का निवेश कर रहे हैं,

एक व्यक्ति के स्टैंड पॉइंट से, बच्चे को शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सौंदर्य रूप से खुद को विकसित करने के लिए सहायता करनी होती है। इसलिए वह एक अच्छे इंसान का जीवन जीने में सक्षम है। शिक्षा का उद्देश्य परिवर्तन लाना है जो छात्रों के जीवन को प्रभावित करेगा, सभी शिक्षकों के लिए एक प्रासंगिक, चिंता का विषय है। वंचित बच्चों के मामले में, चुनौती और भी अधिक है। यह संभावना कि ये बच्चे ग्रामीण और साथ ही साथ स्लम क्षेत्रों में गरीबी की बाधा को दूर करेंगे, लगता है कि स्कूल के कर्मचारी उनकी कितनी प्रभावी सहायता करते हैं। वास्तव में, व्यक्तिगत मार्गदर्शन को प्रभावी मार्गदर्शन सेवा के माध्यम से बढ़ावा और महसूस किया जा सकता है और इन सेवाओं की स्थापना और विकास को स्कूल के व्यक्ति और पारिस्थितिकी की पारिस्थितिकी की सराहना द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

स्वतंत्रता के बाद, सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य केंद्रीय महत्व का था; भारतीय संविधान इसके अनुच्छेद 45 द्वारा (जिसे प्रावधान के साथ प्रतिस्थापित किया गया है बचपन की देखभाल और 86 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा) अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा की। यह विश्वास कि शिक्षा पिछड़ेपन से छुटकारे के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और प्रगति के लिए एक मार्ग भारतीय लोगों के लिए सर्वव्यापी हो गया है। लोगों के बीच शिक्षा की आवश्यकता, फैक्ट्री और जमीन के टिलर के बीच जागरूकता बढ़ रही है, इसके अलावा मध्यम वर्ग के वर्गों में अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए कोलाहल है, क्योंकि वे शिक्षा को मान्यता देते हैं जीवन और सामाजिक पसंद के लिए। और यह व्यापक प्रसार उत्साह शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि से स्पष्ट है।

हालांकि, देश में प्रचलित शिक्षा प्रणाली ऐतिहासिक रूप से कई समस्याओं का सामना करने के लिए किस्मत में है। यह बताना सही है कि कोई भी प्रणाली अलग नहीं रह सकती है और अपने सामाजिक-आर्थिक मैट्रिक्स के प्रभावों से अछूता नहीं रह सकता है। देश में सामाजिक असमानताएँ और विकासात्मक असमानता शैक्षिक



प्रणाली में परिलक्षित होती है। उन छात्रों के बीच अंतर जो 'पहली पीढ़ी' के हैं और जो शिक्षित होम बैकग्राउंड से हैं, सामाजिक-आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सामाजिक-आर्थिक रूप से गरीब और शहरी और ग्रामीण विभिन्न मापदंडों जैसे प्रदर्शन, उपलब्धि, जीविका आदि पर प्रकट होते हैं।

भारत में सामाजिक रूप से वंचित लोगों पर शोध भारत और पश्चिमी देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतरों- ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक- पर ध्यान आकर्षित करता है। किसी समाज के निचले तबके से जुड़े लोग सांस्कृतिक रूप से वंचित हैं। वर्षों की उपेक्षा, भेदभाव और शोषण ने उन्हें सबसे वंचित तबका बना दिया है। गरीब उपलब्धि और खराब बौद्धिक कामकाज समुदाय के इन वंचित वर्गों के बच्चों की मुख्य विशेषताएं हैं। ये बच्चे अक्सर घर पर, समुदाय में और साथ ही स्कूल में अधिकतम अप्रासंगिक कुंठा का सामना करते हैं। एक समय था जब ये बच्चे नहीं थे स्कूलों में जाने की अनुमति। घर में भूख और गरीबी पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था, स्कूल में लगातार असफलता और अस्वीकृति, समुदाय और अवसर में कमी।

यह समस्या सांस्कृतिक नुकसान के व्यापक संदर्भ में आती है। निम्न वर्ग की संस्कृति को अनुभवी दुनिया के सरलीकरण, अभाव, अनिश्चितता और असहायता की विशेषता है। गरीब शायद ही कभी नेतृत्व या जिम्मेदारी की भूमिका निभाते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए सीमित और मामूली लक्ष्य हैं। वे अपने जीवन को लेकर अनिश्चित हैं। यहां न तो नौकरी की सुरक्षा है और न ही आवासीय सुरक्षा। इसके अलावा, वे शक्तिहीन और असहाय हैं। उन्हें उज्वल भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है। वे वर्तमान के साथ संबंध रखते हैं। छात्रों की यह श्रेणी आत्म-अवधारणा, प्रेरणा, सामाजिक जीवन, भाषा और बौद्धिक प्रदर्शन के संबंध में उनके काउंटर भागों से भिन्न होती है।

शिक्षा अपने मिशन को पूरा नहीं कर सकती है और समाज तब तक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वंचित समूहों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ठीक से संबोधित नहीं किया जाता है। इसके लिए भारी संसाधनों के अलावा समर्पण, भागीदारी और नवाचार की आवश्यकता होती है। रेडीमेड ब्लू प्रिंट को खोलना नासमझी है। उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त रणनीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने की आवश्यकता है। स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए हमारे संवैधानिक निर्देशों को न केवल नामांकन के लिए समान अवसर प्रदान करने, सुविधाओं की गुणवत्ता में बदलाव, प्रदान किए गए शिक्षण कर्मियों की सेवाओं में वृद्धि या पाठ्यक्रम में बदलाव के माध्यम से, लेकिन मार्गदर्शक शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

शैक्षिक मार्गदर्शन लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। यह सामानों को वितरित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के लिए अनावश्यक प्रगतिशील सहायक उपाय है, लेकिन अभी तक इसे बंद नहीं किया गया है।

वंचित वर्गों के बारे में हमारे संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान लोकतंत्र के आदर्शों को स्वीकार करते हैं। यह शिक्षा को राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी मानता था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निषेध है धर्म, जाति,



जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। इसमें कहा गया है कि "इस लेख में कुछ भी नहीं है या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका जाएगा"।

उद्देश्य

1. सांस्कृतिक रूप से वंचित माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की सीखने की स्थिति की पहचान करने के लिए।
2. उनकी सीखने की स्थिति के आधार पर सांस्कृतिक रूप से वंचित माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की उपलब्धि की तुलना करना।

सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चे

वर्तमान अध्ययन ने सांस्कृतिक रूप से वंचित माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की समस्याओं और समस्याओं के निवारण के लिए एक मार्गदर्शन कार्यक्रम की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चे गरीब माता-पिता के बच्चे होते हैं और उन्हें हीन सांस्कृतिक वातावरण में लाया जाता है जो उन्हें कौशल, दृष्टिकोण और स्वीकार्य व्यवहार से वंचित करते हैं और वे स्कूल में या तो अकादमिक या व्यवहारिक रूप से सफल होने के लिए तैयार होते हैं। सांस्कृतिक रूप से वंचित छात्रों को "घरों में अनुभव होता है जो स्कूलों और बड़े समाज के सीखने की विशेषताओं के प्रकार के लिए आवश्यक सांस्कृतिक पैटर्न को प्रसारित नहीं करते हैं"।

सांस्कृतिक नुकसान के मजबूत शैक्षिक और समाजशास्त्रीय अर्थ हैं। इसका तात्पर्य है शिक्षा की दुनिया में प्रवेश करने में असमर्थता। साक्षरता और संख्यात्मकता आधुनिक संस्कृति के क्षेत्र के लिए बपतिस्मा है। मिलार्ड एच। बैलेक (1965) में गरीबी, अपराधीता, सांस्कृतिक नुकसान के लक्षणों के रूप में समाज की मुख्य धारा द्वारा स्थापित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता शामिल है। सांस्कृतिक रूप से वंचित व्यक्ति वह है जो कला और विज्ञान द्वारा योगदान किए जाने वाले अधिकांश आधुनिक जीवन के खर्चों के लगातार संपर्क और उपयोग से वंचित है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन को स्थिर और अविकसित बनाने के लिए नियत किया जाता है। उनके जीवन को आधुनिक विचारों और विचारों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के समान होने के लिए बर्बाद किया जाता है। लेकिन सांस्कृतिक नुकसान किसी भी तरह की हैवानियत नहीं है।

ऐसे सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक समुच्चय से प्रभावित होने वाले बच्चों को सांस्कृतिक पिछड़ेपन को पार करना होगा। सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चों की विशेषताएं हैं। वे मुख्यधारा के यार्डस्टिक्स द्वारा निर्धारित विफलताओं का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्हें यह भी लगता है कि उनके शिक्षक उनसे सफलता की उम्मीद नहीं करते हैं। उन्हें इस बात का गहरा डर है कि वे अपने शिक्षकों द्वारा दी गई मान्यता और समझ के साथ अभिवादन नहीं करेंगे जिनकी पृष्ठभूमि पूरी तरह से है भिन्न। उन्हें खुद को उन मांगों के साथ समायोजित



करना मुश्किल लगता है जो मौलिक रूप से उनके लिए विदेशी हैं।

कई कमियों और बाधाओं के कारण, एक सांस्कृतिक रूप से वंचित व्यक्ति दुर्भावना के लक्षण दिखाता है। ऐसा व्यक्ति संज्ञानात्मक कौशल में अपेक्षाकृत धीमा है। लेकिन वह बिलकुल भी मूर्ख नहीं है। एक सांस्कृतिक रूप से वंचित व्यक्ति एक भौतिक, ठोस दृष्टिकोण के माध्यम से सीखने के लिए प्रकट होता है। वह या वह अक्सर सैद्धांतिक के बजाय बौद्धिक-विरोधी, व्यावहारिक प्रतीत होता है। सांस्कृतिक नुकसान की एक हड़ताली विशेषता परंपराओं और अंधविश्वासों के लिए एक अंधा प्रतिबद्धता है। ऐसा व्यक्ति अपने अंध विश्वासों के बारे में तर्क करने को तैयार नहीं है।

इस तरह के छात्रों को लेबल करने के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द 1960 के बाद से कई संशोधनों से गुज़रा है। पहले यह 'सांस्कृतिक रूप से वंचित' से बदलकर 'सांस्कृतिक रूप से वंचित' कर दिया गया ताकि यह संकेत दिया जा सके कि ये छात्र संस्कृतिविहीन (संस्कृति से वंचित) नहीं थे बल्कि एक ऐसी संस्कृति में आ गए जिसने उन्हें एक नुकसान में डाल दिया। बाद में, 'सांस्कृतिक रूप से वंचित' को 'शैक्षिक रूप से वंचित' द्वारा बदल दिया गया था ताकि यह इंगित किया जा सके कि छात्रों की संस्कृति को ध्यान में नहीं रखा गया था, लेकिन स्कूल में काम करने के लिए उन्हें तैयार किया गया था। कुछ छात्र स्कूल में सफल होने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि उनकी संस्कृति उन्हें एक शैक्षिक नुकसान में रखती है। वर्तमान अध्ययन शैक्षिक रूप से वंचितों के बारे में अर्थपूर्ण भ्रम से बचने के लिए 'सांस्कृतिक रूप से वंचित' शब्द को बरकरार रखता है। वास्तव में, एक छात्र के सांस्कृतिक नुकसान उसके या उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन में प्रतिबिंबित होते हैं, दो चर के बीच एक कारण-प्रभाव संबंध होता है। सांस्कृतिक नुकसान विभिन्न नियंत्रणों जैसे कि नियंत्रण के बाहरी नियंत्रण, डे-प्रेरणा, खराब आत्म-सम्मान और नकारात्मक आत्म-अवधारणा के माध्यम से शिक्षा में पिछड़ापन पैदा करते हैं।

शैक्षिक मार्गदर्शन कार्यक्रम

वर्तमान अध्ययन सांस्कृतिक रूप से वंचित माध्यमिक छात्रों के विद्यार्थियों को होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक शैक्षिक मार्गदर्शन कार्यक्रम तैयार करने का एक प्रयास था। जांचकर्ता ने सांस्कृतिक नुकसान की रुग्ण स्थिति के निवारण में इसकी प्रभावशीलता का पता लगाकर इसे काफी प्रभावी साबित किया। शैक्षिक मार्गदर्शन को "विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली सहायता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्कूलों में उनके समायोजन, पाठ्यक्रम और स्कूल के चयन के लिए अपेक्षित है"। यह एक प्रकार का मार्गदर्शन है जो किसी की अपनी क्षमताओं और क्षमताओं के अनुसार अलग-अलग वातावरण में अच्छी तरह से समायोजित करने में मदद करता है। यह छात्रों में विकसित करने की कोशिश करता है, उनमें आवश्यक जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करके स्कूल के माहौल को प्रभावी ढंग से समायोजित करने की क्षमता। यह उन्हें उपयुक्त सीखने के उद्देश्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करेगा, शैक्षिक मार्गदर्शन में छात्रों को अपने भीतर के सभी



संसाधनों और दुनिया में उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण बोध में योजनाबद्ध तरीके से अपने भविष्य का पता लगाने में मदद करने की कठिन कला शामिल है, जिसमें वे रहते हैं और काम करते हैं। कुछ विशेषज्ञ इस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। पूरे स्कूल स्टाफ के समर्थन की जरूरत है और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शैक्षिक मार्गदर्शन हर किसी से संबंधित है शिक्षा के पहलुओं जैसे संस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षा के तरीके, अन्य पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ, अनुशासन। शैक्षिक मार्गदर्शन एक नियोजित और उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है जिसे प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित लक्ष्य है। जिन उद्देश्यों के तहत व्यक्ति को सहायता दी जाती है, वे हैं: (i) उसकी क्षमताओं को समझना (ii) विभिन्न शैक्षिक अवसरों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट विचार है (iii) शिक्षण संस्थान और पाठ्यक्रमों के संबंध में समझदारी से चुनाव करें। शैक्षिक मार्गदर्शन के कुछ उद्देश्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं: (क) उसकी क्षमता, सामर्थ्य और सीमाओं को समझने के द्वारा शिष्य को उसे या स्वयं को जानने में मदद करना। (ख) सीखने वाले को उसकी क्षमताओं, रुचियों और लक्ष्यों के अनुकूल शैक्षिक योजनाएँ बनाने में मदद करना। (c) पेशकश किए गए विषय और पाठ्यक्रमों के बारे में छात्र को गहराई से जानने में सक्षम बनाना। (d) अपने अध्ययन में संतोषजनक प्रगति करने में छात्र की सहायता करना। (the) बच्चे को संस्थागत वातावरण में समायोजित करने में मदद करना। (च) बच्चे को अध्ययन की अच्छी आदतें विकसित करने में मदद करना। (छ) बच्चे को कक्षा की शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने में मदद करने के लिए जिसमें वह नेतृत्व और अन्य सामाजिक गुणों का विकास कर सकता है।

वर्तमान शैक्षिक मार्गदर्शन कार्यक्रम केरल में माध्यमिक स्तर पर सांस्कृतिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। इसने सांस्कृतिक नुकसान के पांच आयामों पर जोर दिया है जिन्हें इस अध्ययन के मुख्य चर के रूप में भी स्वीकार किया गया है जैसे कि भाषा अवरोध, सीखने का माहौल, पारिवारिक संबंध, स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, इस कार्यक्रम की कल्पना की गई और इसे निम्नलिखित के साथ लागू किया गया। उद्देश्यों।

1. शिक्षा के नए उद्देश्य के लिए खुद को उन्मुख करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना।
 2. अच्छी योजना के लिए खुद को उन्मुख करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना।
 3. अध्ययन के विषयों के बुद्धिमान विकल्प बनाकर खुद को अपनी शिक्षा में समायोजित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना।
 4. विषय की कठिनाइयों और अच्छे अध्ययन कौशल के विकास को हटाकर विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में प्रगति करने के लिए सहायता करना
 5. अध्ययन के लिए उचित प्रेरणा का निर्माण करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना
- 1.1 अध्ययन की आवश्यकता और महत्व



भारतीय शिक्षा अभी जीवित रहती है, जब वह भारत के संविधान की आकांक्षाओं और आदर्शों को पूरा करने का प्रयास करती है। हमारा संवैधानिक मिशन भारत को एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, सामाजिक-आर्थिक राष्ट्र के रूप में डिजाइन करना है। स्वाभाविक रूप से, हमारी सार्वजनिक वित्त पोषित शिक्षा उस भव्य उद्देश्य के अधीन होने के लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए। इसलिए, अवधारणाओं- पहुंच, इच्छिटी और गुणवत्ता को हमारी शैक्षिक प्रणाली के तीन मौलिक कार्यात्मक मानदंडों के रूप में मान्यता दी गई है। हमारे संविधान की समतावादी भावना हमारे पाठ्यक्रम फ्रेम में परिलक्षित होती है जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर काम करती है। समय के साथ, भारतीय शिक्षा ने औपनिवेशिक और अभिजात्य वर्ग को औपनिवेशिक आकाओं से अलग कर दिया। गली में आदमी की प्रगति के रूप में देश की समग्र प्रगति का संकेत बन गया है, हमारे राष्ट्र के गरीब और हाशिये के वर्गों की शैक्षिक उन्नति हमारी शैक्षिक प्रगति का वास्तविक प्रमाण बन गई है। इसलिए, सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चों के शैक्षिक मुद्दों को संबोधित करना हमारी शैक्षिक प्रणाली का एकमात्र कर्तव्य है। इस संबंध में व्यावहारिक उपायों को डिजाइन और कार्यान्वित किया जाना है।

सार्वजनिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण कार्य वंचितों और वंचितों के हितों की रक्षा करना और तदनुसार सार्वजनिक संसाधनों को वितरित करना है। स्वतंत्रता के बाद से, भारत में नीतियों को क्षेत्रीय, सामाजिक-आर्थिक और लैंगिक असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ तैयार किया गया है। पिछड़े वर्गों और समुदायों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम और परियोजनाएं शुरू की गई हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों के सांस्कृतिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं और जरूरतों पर थोड़ा ध्यान दिया गया है।

नई शिक्षा नीति (1986) में जोर दिया गया है कि सभी क्षेत्रों से सभी असंतुलन और असमानताएं दूर की जानी चाहिए। नीति विशेष रूप से छोटे बच्चों, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के विकास में निवेश पर जोर देती है क्योंकि शिक्षा किसी भी देश की जनसांख्यिकी में प्रमुख स्थान रखती है। वे कल के नागरिक हैं। उनकी वर्तमान स्थिति उनके वयस्कता के भविष्य को आकार देती है। किसी भी राष्ट्र का विकास उसके बच्चों के विकास पर निर्भर करता है। कई वंचित छात्र अपने शुरुआती स्कूल के वर्षों में बुनियादी शैक्षिक कौशल जैसे कि पढ़ना, लिखना और अंकगणित में महारत हासिल नहीं करते हैं। उनके घरों और समुदायों में आशाहीनता कक्षा में कई बार परिलक्षित होती है। क्योंकि वे आसानी से पढ़ते या समझते नहीं हैं, वे अपने वर्ग के काम के साथ नहीं रह सकते हैं।

अधिक प्रभावी मार्गदर्शन कार्यक्रम अनिवार्य हैं, यदि वंचित, विकलांग और अल्पसंख्यक छात्रों को इस देश में इस व्यक्तिगत और कैरियर की क्षमता का एहसास करना है। वर्तमान में इन छात्रों को उनके सांस्कृतिक विकास में सांस्कृतिक अंतर, मूल्य, भाषा अंतर, सीमित शैक्षणिक उपलब्धि और व्यावसायिक प्रेरणा द्वारा बाधित किया जाता



है। शैक्षिक और रोजगार सेटिंग्स में विशेष आवश्यकताओं के लिए समान अवसर प्रदान करना हाल के दशकों में हमारे समाज का एक प्रमुख लक्ष्य बन गया है। कई मामलों में, कुछ निर्णय लेने के कौशल जैसे कि आत्म मूल्यांकन, विकल्प चुनना और लक्ष्य निर्धारण में निर्देश आज के छात्रों के सीखने के अनुभव में कमी है। यह विशेष रूप से विशेष आबादी का सच है जैसे कि विकलांग, वंचित और जिनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस देश में बहुमत से भिन्न है।

इन विशेष आबादी की मार्गदर्शन आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता प्राप्त करनी चाहिए, यदि उन्हें अपनी व्यक्तिगत और कैरियर की क्षमता का एहसास हो। अधिक प्रभावी मार्गदर्शन कार्यक्रम विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में जरूरी हैं कि ये आबादी बढ़ रही है क्योंकि यह देश समतावाद की ओर बढ़ता है। समतावाद की ओर इस आंदोलन को पब्लिक स्कूलों के समर्थन के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्र के व्यापक शैक्षिक मिशन को राज्य और स्थानीय स्तरों पर प्रभावी नेतृत्व के माध्यम से सुनिश्चित करना है, उन सीखने के अनुभवों को जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुकूल हैं। जो सभी छात्रों के लिए निरंतर शैक्षिक और / या रोजगार को बढ़ावा देगा।

निष्कर्ष

इस अध्याय में अध्ययन का एक संक्षिप्त सारांश शामिल है, इसके बाद प्रमुख निष्कर्ष और निष्कर्ष पर पहुंचे, अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ और आगे के शोध के लिए सुझाव। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य सांस्कृतिक रूप से वंचित माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षिक मार्गदर्शन कार्यक्रम तैयार करना था। इस अध्ययन के विभिन्न पहलुओं को निम्नलिखित प्रमुखों के अंतर्गत संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

ग्रंथ सूची

- [1] अग्रवाल, ए। (2000)। अनुसूचित जाति के छात्रों की कुछ शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 19 (1), 37-41।
- [2] अग्रवाल, ए।, और सिरमफ़ा, सी। (2003)। स्लम क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकता को प्राप्त करना: समस्याएं और मुद्दे। जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, 33 (4), 55-60।
- [3] अग्रवाल, जेसी (1996)। एक विकासशील समाज में शिक्षक और शिक्षा। नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा। लिमिटेड
- [4] अग्रवाल, वाईपी, और सुनीता, सी। (2003)। दिल्ली में झुग्गी के बच्चों की उपलब्धि। नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान।
- [5] अहमद, एस।, और जोशी, आरके (1977)। स्कूल जाने वाले बच्चों में गैर-रचनात्मक रचनात्मक सोच क्षमता पर सामाजिक-सांस्कृतिक नुकसान का प्रभाव। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, 52 (4), 342-349।



- [6] अलका, एजीए (2011)। माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए एक मेटा-संज्ञान एकीकृत मल्टीमीडिया विज्ञान शिक्षण पैकेज तैयार करना (अप्रकाशित डॉक्टरेट शोध प्रबंध)। कर्टिन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय।
- [7] एलन, डब्ल्यूजी (1978)। घर का वातावरण और प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास: एक अनुदैर्घ्य अनुसंधान। शिकागो: मार्क्सम।
- [8] अल्टेकर, एएस (1934)। प्राचीन भारत में शिक्षा। बनारस: द इंडियन बुकशॉप।
- [9] अम्बष्ट, एनके (2001)। जनजातीय शिक्षा: समस्याएं और मुद्दे। नई दिल्ली: वेंकटेश प्रकाशन।
- [10] अम्बष्ट, एनके, और रथ, केबी (1995)। प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण और उपलब्धि पर घरेलू सामुदायिक और स्कूल कारकों के प्रभाव का अध्ययन। नई दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी.
- [11] अमीर्जन, एमएस, और थिमप्पा, एमएस (1993)। सामाजिक-आर्थिक स्तर और जाति संबद्धता के रूप में विस्तार और विक्षिप्तता। जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, 37 (3), 26-29।
- [12] आनंद, जी। (1995)। आदिवासी बच्चों के बीच प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय। प्राथमिक शिक्षक, 20 (1), 37-41।